दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स राजस्थान

जुलाई (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- एमएसएमई क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिये करौली ज़िला हुआ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित 3
- राजस्थान में बनेगा 10,000 मेगावाट का अल्ट्रामेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क 3
- प्रदेश में बोटेनिकल गार्डन 4
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ 4
- बीकानेर के देराजसर एवं सातलेरा में खुलेंगे नवीन आयुर्वेद औषधालय 4
- राजफैड एवं पीएनबी के मध्य एमओयू 5
- 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में राजस्थान पंद्रहवें स्थान पर 5
- 'राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम' (दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान) पुस्तक 6
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को समूचे प्रदेश में लागू करने के लिये बैठक आयोजित 6
- राजस्थान सरकार और जापान की 11 कंपनियों के मध्य एमओयू 6
- प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिये 16.50 करोड़ रुपए स्वीकृत 7
- डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का इंटरनेशनल वेबिनार 8
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 8
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन पोर्टल का शुभारंभ 9
- 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम का शुभारंभ' 9
- जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में खुलेगा फोरेंसिक साइंस संस्थान 10
- मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की 10
- फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री युवा इकाई का समारोह आयोजित 11
- जयपुर में लागू हुई 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना' 11
- कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 12
- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम व इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण 13
- ट्रैवल प्लस लेज़र की विश्व के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर 13
- 18वाँ अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय सम्मेलन 14
- डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू किये गए 'ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट' की समीक्षा 14
- प्रदेश में खुलेंगे 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय 15
- छबड़ा एवं कालीसिंध में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट होंगे स्थापित 15
- नई दिल्ली में कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी की शुरुआत 15
- उत्सव पोर्टल पर राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी, राजस्थान चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य 16
- मुख्यमंत्री ने किया जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास 17
- राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन 17
- जोधपुर में बनेगी पैरा खेल अकादमी 18
- 'पैलेस ऑन व्हील्स' फिर से दौड़ेगी पटरियों पर 18
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट- 2022 19
- उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में बनेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन 19
- 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी 20
- राज्य में प्रथम महिला निधि वित्तीय संस्थान के लिये एमओयू 20
- 'घर-घर औषधि योजना'का होगा विस्तार 21
- 'राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर्स रूल्स, 2017' में संशोधन को मंज़ूरी 21
- राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन 22
- परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार 22
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में संशोधन को मिली मंज़ूरी 22
- हेपेटाइटिस अभियान के तहत राजस्थान को मिला राष्ट्रीय सम्मान 23
- भीलवाड़ा ज़िले के मांडल में 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण 24
- चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा 24
- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण 25
- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर 25

नोट :

राजस्थान

एमएसएमई क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिये करौली ज़िला हुआ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली जिले को 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' की श्रेणी में दूसरा स्थान पाने के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये दिए गए 26 श्रेणी के पुरस्कारों में राजस्थान ने 4 अलग-अलग श्रेणियों में कब्जा जमाया।
- प्रधानमंत्री ने दिव्यांग विजेता सुनीता गुप्ता के साथ चर्चा की। इस दौरान अशोक पारीक एवं अनीता लूनिया को भी विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य के लिये सम्मानित किया गया।
- राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि एमएसएमई नीति में बदलाव के चलते किसी भी उद्योगपति को अब उद्योग स्थापित करने के लिये 3 से 5 वर्ष तक विभिन्न विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- उद्योग मंत्री ने कहा कि आगामी 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश में विभिन्न कंपनियों द्वारा निवेश किया जाएगा। इससे न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिये रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
- गौरतलब है कि राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिलों को 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' कार्यक्रम के तहत चयन किया जा चुका है, जिनमें से करौली जिले ने बेहतरीन कार्य के लिये दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टस' कार्यक्रम भारत सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना है, जिसके जरिये देश के प्रगतिशील जिलों को क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य के लिये चुना जाता है।

राजस्थान में बनेगा 10,000 मेगावाट का अल्ट्रामेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को राजस्थान सरकार एवं एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रामेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPP) विकसित करने हेतु जयपुर में समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि प्रदेश में अनुपयोगी बंजर भूमि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता तथा देश की सर्वाधिक सौर विकिरण की उपलब्धता भी प्रदेश में निजी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
- प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राजस्थान में निजी निवेशकों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के कारण कृषकों की जमीन दर में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
- एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड के सीईओ मोहित भार्गव ने बताया गया कि इस परियोजना की स्थापना पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- प्रदेश में अल्ट्रामेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने का काम एनटीपीसी रिन्यूअल एनर्जी लिमिटेड करेगी। एनटीपीसी लिमिटेड 100% सब्सिडी कंपनी है, जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के व्यवसाय को आगे ले जाने के लिये बनाई गई है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान देश भर में 18,701 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में 13,332 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएँ स्थापित हो चुकी हैं।

नोट :

प्रदेश में बोटेनिकल गार्डन

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को राजस्थान वन विभाग प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के छः संभाग मुख्यालय के जिलों में बनने वाले बोटेनिकल गार्डन एवं संशोधित लव-कुश वाटिकाओं के जिला उप-वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनके जल्द निर्माण की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में स्थानीय प्रजातियों के पौधों, जैवविविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के छह संभाग मुख्यालय के अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं जोधपुर जिलों में बोटेनिकल गार्डन का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।
- इन गार्डनों में अधिक-से-अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे एवं वनस्पतियाँ लगाई जाएंगी। साथ ही, लव-कुश वाटिकाओं के तहत स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल वहा की स्थानीय वनस्पतियाँ, जैसे- फल, फूल, औषधीय एवं छायादार पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को वहाँ का स्थानीय वनानुभव मिल सके।
- बोटेनिकल गार्डन एवं लव-कुश वाटिकाओं के निर्माण की संरचना एवं आकार-प्रकार के निर्माण कार्य में अधिक-से-अधिक प्राकृतिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा, ताकि यह लोगों को प्रकृति का एहसास करा सके।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को राजस्थान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि गत वर्ष इस योजना के माध्यम से 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान था, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष हेतु 15 हजार कर दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष योजनांतर्गत सीए एवं सीएस पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् भी दो वर्ष तक विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा ने बताया कि योजना अंतर्गत विद्यार्थी 31 जुलाई, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गत वर्ष योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के कुल 1,09,510 आवेदन प्राप्त हुए थे।
- नवीन पोर्टल पर अब समस्त दस्तावेजों का यथासंभव वेबसर्विस से सत्यापन होगा। आवेदन पत्रों का यथासंभव स्वतः अनुमोदन होने से आवेदन की अंतिम तिथि के तत्काल पश्चात् वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वरीयता सूची में 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची का भी प्रावधान रखा गया है।

बीकानेर के देराजसर एवं सातलेरा में खुलेंगे नवीन आयुर्वेद औषधालय

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर ज़िले के ग्राम पंचायत मुख्यालय देराजसर तथा ग्राम सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'आयुष नीति-2021' में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन आयुर्वेद औषधालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

नोट :

- आयुष विभाग द्वारा आयुष नीति-2021 के मापदंडों के आधार पर ग्राम पंचायत मुख्यालय देराजसर में नवीन आयुर्वेद औषधालय स्थापित करने तथा सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने हेतु शिथिलता प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
- सरकार के इस निर्णय से लोगों को ग्राम स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

राजफैड एवं पीएनबी के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं प्रशासक राजफैड श्रेया गुहा की उपस्थिति में राजफैड सभागार में राजफैड एवं पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एमओयू संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू के माध्यम से पीएनबी राजफैड को 2 हज़ार करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराएगा।
- एमओयू पर राजफैड की ओर से वित्तीय सलाहकार उषस्पति त्रिपाठी एवं पीएनबी की ओर से मुख्य प्रबंधक निखिल ने हस्ताक्षर किये।
- राजफैड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजोरिया ने बताया कि राजफैड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने, समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने सहित अन्य गतिविधियों के लिये पीएनबी के साथ एमओयू किया है।

'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में राजस्थान पंद्रहवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में राजस्थान पूरे देश में पंद्रहवें स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में राजस्थान 694 स्कोर के साथ पंद्रहवें स्थान पर है।
- विशेषश्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा, तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति तथा प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

नोट :

'राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम' (दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान) पुस्तक

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2022 को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल ने अपनी पुस्तक 'राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम' एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद 'दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान' की प्रथम प्रति भेंट की।

प्रमुख बिंदु

- निदेशक पन्नालाल मेघवाल ने बताया कि 'राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम' पुस्तक में राजस्थान के लोकनृत्यों, लोकगायन एवं लोकवादन की परंपरा के बारे में शोधपरक जानकारियाँ शामिल की गई हैं।
- इस पुस्तक में राजस्थान के तेरहताली, घूमर, चरी, कालबेलिया, चकरी, भवाई, जसनाथी, धाकड़, गींदड, वीर तेजाजी, कच्छी घोड़ी, कथौड़ी, भील, गरासिया, गैर, चंग, बम, ढोल एवं शूकर लोकनृत्य सम्मिलित हैं।
- पुस्तक में मांड, मांगणियार एवं लांगुरिया गायन, तुर्रा कलंगी, कुचामणि ख्याल एवं गवरी लोकनाट्य, सहरिया एवं टूंटिया स्वांग, बीकानेर की रम्मतें, राजस्थान की नट परंपरा, कठपुतली नृत्य कला एवं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का विषद विवेचन किया गया है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को समूचे प्रदेश में लागू करने के लिये बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को समूचे राजस्थान में लागू करने के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास, बाल आधिकारिता तथा आयोजना मंत्री ममता भूपेश की अध्यक्षता में चिल्ड्रेंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) तथा सहयोगी संस्था आईपीई ग्लोबल के साथ बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं के लिये लागू करने की घोषणा के अनुसार आने वाले समय में इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर 6 हज़ार रुपए की राशि महिलाओं को जच्चा-बच्चा पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिये दी जाती है। यह राशि सीधे ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राजस्थान सरकार का समूचे देश में अनूठा नवाचार है।
- राज्य के टीएसपी क्षेत्र के पाँच ज़िलों में जहाँ अति कुपोषित बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पिछले साल से 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को चलाया गया है। योजना को संचालित करने में सीआईएफएफ और आईपी ग्लोबल संस्था सहयोग प्रदान कर रही है।
- गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभागों में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग के उद्देश्य से चिल्ड्रेंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) राजस्थान सरकार के साथ अनुबंध के आधार पर कार्य कर रही है।
- इसके अंतर्गत सीआईएफएफ के माध्यम से सहयोगी संस्था आईपीई ग्लोबल राजपुष्ट कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग को 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' एवं 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण' के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

राजस्थान सरकार और जापान की 11 कंपनियों के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2022 को नीमराना स्थित डाईकिन जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग एक्सिलेंस (डीजेआईएमई) में आयोजित एमओयू सेरेमनी में राजस्थान सरकार और जापान की 11 कंपनियों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू से नीमराना, गिलोठ व चापारिया की ढाणी (पाली) क्षेत्रों में 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2272 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- राजस्थान सरकार ने जापान की जिन 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं, वे हैं- टोकाई रिका मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (335 करोड़ रुपए), निडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (300 करोड़ रुपए), हिताची एस्टेमो राजस्थान ब्रेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (140 करोड़ रुपए), फूजी सिल्वरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (110 करोड़ रुपए), सीकेडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (100 करोड़ रुपए), ताइयो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (100 करोड़ रुपए), एलाइड जेबी फ्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड (78 करोड़ रुपए), एच2 मिल्क फार्म प्राइवेट लिमिटेड (65 करोड़ रुपए), एचएनवी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (40 करोड़ रुपए), एमआईईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (40 करोड़ रुपए) एवं बेलटेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (30 करोड़ रुपए)।
- इस एमओयू से लगभग 1300 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो कि 22 बिलियन येन के बराबर है। प्रदेश में वर्ष 2008 में जापान की कंपनियों की संख्या 10 थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 170 हो गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जापान की कंपनियों को बाड़मेर में बन रहे, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इनवेस्ट राजस्थान और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने जापान की कंपनियों से आह्वान किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी रोज़गार देने के लिये स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले, इनमें जो भी अपेक्षित सहयोग होगा, राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की वर्ष 2005 में जापान यात्रा के दौरान जापानी निवेश, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) व फ्रंट कॉरिडोर की भूमिका तैयार हुई थी। नीमराना स्थित जापानीज़ ज़ोन भी डीएमआईसी का हिस्सा है।
- भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने कहा कि भारत और जापान कानून का शासन एवं लोकतंत्र जैसे मौलिक मूल्यों को साझा करते हैं। हमारा रिश्ता केवल द्विपक्षीय नहीं है, अपितु असाधारण है। इसीलिये इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप कहते हैं।
- उन्होंने कहा कि गत मार्च में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच समिट में इस बात पर संतोष जताया गया कि वर्ष 2014 में घोषित किये गए 5 ट्रिलियन जापानीज़ येन (लगभग 2 लाख करोड़ रुपए) के निवेश का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अब 5 ट्रिलियन जापानीज़ येन (लगभग 3 लाख करोड़ रुपए) को आगामी 5 वर्षों में जापान द्वारा भारत में निवेश करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि उद्योग विभाग ने हाल ही में प्रत्येक ज़ले में रोड शो का आयोजन किया, जिससे वहाँ के पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 हज़ार से ज़्यादा उद्यमी 7 एवं 8 अक्टूबर को प्रस्तावित इनवेस्ट राजस्थान समिट में भाग लेंगे। इससे प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलेंगे।
- जापानीज़ एक्सटर्नल ऑर्गेनाईज़ेशन (जेट्रो) के मुख्य महानिदेशक यासुयुकि मुराहाशि ने कहा कि जापान की कंपनियों द्वारा किये गए एमओयू से राजस्थान में लगभग 1300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि इनमें से 1 कंपनी गिलोठ इंडस्ट्रियल पार्क में निवेश करने जा रही है, जो कि किसी जापान की कंपनी का उक्त क्षेत्र में पहला निवेश है।

प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिये 16.50 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिये 16 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार गिर्वा (उदयपुर), केरू (जोधपुर), हिंडौन (करौली), धोद (सीकर), परबतसर (नागौर), परसरामपुरा (झुंझुनूँ), बानसूर (अलवर), रूपवास (भरतपुर), उच्चौन (भरतपुर), तारानगर (चूरू) तथा बगरू (जयपुर) में नए खेल स्टेडियम का निर्माण होगा।
- प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किये जाएंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम (आरएसआरडीसी) तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से नए बनने वाले सभी खेल स्टेडियमों में 200 मीटर का सिंडर एथलीटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो-खो व कबड्डी के मैदान आदि खेल सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। साथ ही, ढाँचागत सुविधाओं के रूप में स्टेडियम कार्यालय की बिल्डिंग, टॉयलेट ब्लॉक, ट्यूबवेल, आंतरिक सड़कें व चारदीवारी आदि का निर्माण भी होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में नए खेल स्टेडियमों का निर्माण करने की घोषणा की थी।

डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का इंटरनेशनल वेबिनार

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2022 को इंडियन डेल्फिक काउंसिल एंड इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का चैप्टर 'डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान' का एक वर्ष पूरा होने पर इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में वक्ताओं ने डेल्फिक की गतिविधियों को बढ़ाने पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु

- डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष आईएएस श्रेया गुहा ने बताया कि काउंसिल द्वारा डेल्फिक डायलॉग की सीरीज 'डीसीआर@: द रोड अहेड' के तहत इस ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया।
- इंडियन डेल्फिक काउंसिल के सचिव आईएएस शांतनु अग्रहारी ने बताया कि वर्ष 2023 में डेल्फिक नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा तथा जनवरी 2023 से डेल्फिक के स्टेट गेम्स की शुरुआत होगी। वेबिनार में वक्ताओं ने डेल्फिक की गतिविधियों को बढ़ाने पर चर्चा की।
- गौरतलब है कि डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान कला को प्रोत्साहित व संरक्षित करने में एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य कर रहा है, जिससे न केवल विलुप्त होती कलाओं को आधार मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी के लिये कला आधार सेतु भी बनेगा।

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2022 को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि 'राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम)' का आयोजन 22 से 24 जुलाई तक किया जाएगा। 22 जुलाई से ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ कार्यक्रम होटल क्लार्क्स आमेर में होगा।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट में दो दिन राजस्थान से जुड़े एग्जिबिटर्स और पैन इंडिया के बायर्स के बीच बी2बी बैठकें होंगी। ट्रैवल मार्ट में लगभग 200 एग्जिबिटर्स अपने पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स भाग लेंगे। ये ट्रैवल मार्ट पर्यटन क्षेत्र के लिये काफी लाभदायक साबित होंगे।
- पर्यटन मंत्री ने बताया कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के उद्घाटन समारोह में 'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति' का विमोचन भी किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने और राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाई गई है।
- इससे प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों एवं युवाओं को रोज़गार तथा राजस्थानी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सब्सिडी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) एवं राज्य सरकार के अधीन स्मारकों पर देय फीस में छूट सहित अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।
- गौरतलब है कि आरडीटीएम में डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को आमंत्रित करने के लिये प्रदेश के जयपुर, मंडावा, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर ज़िलों में रोड शो का आयोजन किया गया।

नोट :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिये नवीन पोर्टल में कई नए प्रावधान किये गए हैं। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान हो जाना नवीन पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है।
- उन्होंने कहा कि इस बार जुलाई माह में ही छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला गया है, ताकि विद्यार्थी अपने कॉलेज/संस्थान में प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकें।
- विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि नवीन पोर्टल में फीस रसीद विलोपित कर पाठ्यक्रमवार पुनर्भरण योग्य राशि का पोर्टल द्वारा स्वत: गणना कर प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान करते हुए राजकीय संस्थानों के समस्त व निजी संस्थानों के केवल नवीनीकरण आवेदन-पत्रों को ज़िला कार्यालय पर स्वत: सत्यापन की व्यवस्था प्रभावी की गई है।
- नवीन पोर्टल के तहत शिक्षण संस्थान के पेज पर पाठ्यक्रमवार व कक्षावार फीस स्ट्रक्चर पूर्व में ही भरने व तद्नुसार छात्रवृत्ति भुगतान तथा आधार बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही आवेदन अग्रेषण/सत्यापन व स्वीकृति की व्यवस्था की गई है।
- इस बार आवेदन-पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिये विद्यार्थी व शिक्षण संस्थान को प्रत्येक 7 दिवस में चेतावनी संदेश प्रसारित किया जाएगा व आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर 30 दिवस में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- इसके साथ ही आवेदन-पत्रों की मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन की स्थिति में वेरीफाई स्तर पर आवेदनों को जाँचने की समय-सीमा को 10 दिवस व ज़िलाधिकारी स्तर पर 10 दिवस तक किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- नवीन पोर्टल पर मार्च 2020 से विद्यार्थी के गत वर्षों के आवेदन का विवरण विद्यार्थी के आवेदन पर ही सत्यापनकर्त्ता को प्रदर्शित किये जाने के कारण गैप प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस बार योजना में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के नवीन दिशा-निर्देशानुसार विद्यार्थी की छात्रवृत्ति की सुनिश्चितता हेतु पोर्टल पर फ्रीशिप कार्ड का प्रावधान किया गया है, ताकि इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपना विवरण अंकित करने पर उसकी पात्रता का स्वत: सत्यापन होकर स्वत: एक फ्रिशिप कार्ड जारी होगा।
- नए प्रावधानों के तहत अगले शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति या पदोन्नति के आधार पर छात्र का छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु स्वत: आवेदन होगा तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रवेश व परीक्षा के डेटाबेस को डिजिलॉकर डाटाबेस से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, ताकि पोर्टल इस डाटाबेस से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो, ताकि स्वीकृति व नवीनीकरण हेतु छात्र की पात्रता भी निर्धारित हो सके।

'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम का शुभारंभ'

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिये रेमेडिएशन कार्यक्रम 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम का पोस्टर व लोगो भी जारी किया। साथ ही शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों के लिये 'फील्ड ओरिएंटेशन' कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिये शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु रेमेडिएशन कार्यक्रम 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आयोजित ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित, आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन करवाया जाएगा।

नोट :

- गौरतलब है कि कोविड के कारण हुई नौनिहालों की शैक्षिक क्षति की भरपाई के लिये वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान से 'ब्रिज कार्यक्रम' की घोषणा की गई थी।
- 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 के लिये प्रथम तीन माह में 4 कालांश तथा शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश निर्धारित रहेंगे।
- योजनांतर्गत 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिये दक्षता आधारित कार्यपुस्तिकाएँ तैयार की जाएंगी तथा वर्ष में 3 बार दक्षता का आकलन किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत नियमित शिक्षक-अभिभावक बैठकों के साथ विद्यार्थियों के दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे।
- इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम संचालित होंगे तथा कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों हेतु टीचिंगएड ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में खुलेगा फोरेंसिक साइंस संस्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में फोरेंसिक साइंस संस्थान के लिये 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस (SPUP) द्वारा संयुक्त रूप से फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसमें नए कैंपस के निर्माण तथा यूनिवर्सिटी की वर्तमान बिल्डिंग तथा संसाधनों का उपयोग कर कुछ चयनित कोर्स अकादमिक सत्र-2022-23 से ही शुरू करने के लिये केंद्र सरकार को लिखा है।
- इसके साथ ही प्रदेश में संभागीय स्तर पर कुछ महाविद्यालयों को आने वाले समय में एनएफएसयू, राजस्थान से संबद्ध किये जाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना से अपराध एवं न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता संवर्द्धन एवं अनुसंधान के नए आयाम स्थापित होंगे। साथ ही इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में फोरेंसिक विज्ञान के बढ़ते महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन में पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार तथा 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार दिये जाएंगे। अभी तक इन पुरस्कारों में विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता रहा है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई, 2022 को सवाई मानसिंह स्टेडियम में लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह के दौरान पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
- गौरतलब है कि वर्ष 2014 में महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 50 हज़ार हज़ार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई थी। मुख्यमंत्री के अहम फैसले से पुरस्कार राशि में अब पाँच गुना बढ़ोतरी हो गई है।

नोट :

- गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985-86 में की गई थी तथा अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1982-83 में की गई थी तथा इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है।
- ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये ओलंपिक पदक विजेताओं के लिये इनामी राशि बढ़ाई थी। इसमें पदक विजेताओं की इनामी राशि, स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए की गई।
- इसी तरह एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली 30 लाख, 20 लाख एवं 10 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ाकर क्रमश: 1 करोड़, 60 लाख एवं 30 लाख रुपए की जा चुकी है।
- मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिये राज्य में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न पॉलिसी के आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्तियाँ देने का भी निर्णय लिया गया था। इसमें अभी तक 229 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियाँ दी जा चुकी है।

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री युवा इकाई का समारोह आयोजित

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के आतिथ्य में मेरिएट होटल में वाणिज्य एवं उद्योग संगठन 'फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (फोर्टी) युवा इकाई का समारोह आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और खुशहाल राजस्थान के निर्माण के लिये लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ नवाचार अपनाते हुए युवा स्टार्टअप्स के लिये वातावरण बनाए जाने का आह्वान किया।
- राज्यपाल ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि, अच्छी पैकेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रभावी विपणन पर बल दिया जाए, तो भारत निश्चित ही विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन कर उभरेगा।
- उन्होंने महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिये भी कार्य किये जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को डिजिटल तकनीक के ज़रिये कैसे विश्व बाज़ार तक पहुँचाया जाए और कैसे महिला उद्यमिता को हर स्तर पर बढ़ावा मिले, इसके लिये कार्य किया जाए।
- राज्यपाल ने कोविड के दौर से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिये आर्थिक राष्ट्रवाद पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अर्थतंत्र, श्रमशक्ति और पूँजी-निर्माण पर घरेलू नियंत्रण इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
- उन्होंने कहा कि लघु, अति लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास से ही 'आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग प्रशस्त होगा। स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बनाते हुए वैश्विक बाज़ार तक पहुँचाने के लिये प्रभावी प्रयास करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फोर्टी सहित वाणिज्यिक संगठनों को परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े गाँवों को सूचीबद्ध कर यहाँ के स्थानीय उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करवाने की पहल करनी चाहिये।

जयपुर में लागू हुई 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना'

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से ऋणियों के लिये 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना-2022-23' लागू की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का लाभ जयपुर ज़िले के ऋणी ले सकेंगे, जिसके तहत 31 मार्च, 2022 तक वितरित व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिये पात्र होंगे।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
- योजना के तहत पात्र ऋणियों को अधिशेष राशि (मूल व ब्याज) एकमुश्त जमा कराने पर दंडनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट देय होगी।

कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस

चर्चा में क्यों ?

14 जुलाई, 2022 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बंगलुरू में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 'समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान' की सोच के साथ कृषि के लिये अलग से बजट पेश किया गया, जिसमें कृषक कल्याण कोष की राशि 2 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार करोड़ रुपए की गई है।
- विगत साढ़े तीन साल में 150 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसीधारक कृषकों को 16 हज़ार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किये गए।
- खरीफ 2021 से फसल बीमा पॉलिसियाँ वितरित करने वाला राजस्थान देश में प्रथम राज्य है। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को इसका अनुसरण करने के निर्देश दिये हैं।
- कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा 'राज किसान साथी पोर्टल' बनाया गया है, जो किसानों एवं कृषि व्यवसायियों के लिये एकल खिड़की के रूप में काम कर रहा है। इसमें कृषि से संबंधित सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सूचनाएँ, अनुदान सहायताएँ, लाइसेंस एवं पंजीयन आदि की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को हस्तांतरित किये गए हैं।
- 'राजस्थान जैविक खेती मिशन' के लिये कृषि बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 3 लाख 80 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। कृषि विपणन प्रसंस्करण व निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्य में कार्यरत् 120 कृषक उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राज्य की सभी कृषि उपज मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 136 मंडी समितियों में ऑयल टेस्टिंग मशीन, ग्रेन फिजिकल एनालाइजर मशीन एवं वेईंग स्केल मशीन आदि उपकरणों की स्थापना की जा चुकी है।
- नेनो यूरिया (तरल) उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये ज़िलास्तरीय कार्यशालाएँ एवं किसान गोष्ठियों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अब तक राज्य में 17 लाख नेनो यूरिया बॉटल्स का वितरण किया जा चुका है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि बाजरा, ज्वार और अन्य छोटे मिलेट्स के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये 'राजस्थान मिलेट संवर्धन मिशन' शुरू किया गया है। इसको प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी।
- जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2021-22 के दौरान 1 लाख किसानों को नि:शुल्क जैव उर्वरक का वितरण किया गया। सरकार द्वारा डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में पहले जहाँ 50 लाख मीट्रिक टन एस.एस.पी. का उपयोग होता था, वहीं इस वर्ष रिकॉर्ड 7.10 लाख मीट्रिक टन एस.एस.पी. का वितरण हुआ।
- कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री कटारिया ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बैंकों द्वारा पोर्टल पर गलतियों के कारण पिछले वर्षों में 1 लाख 10 हज़ार प्रकरण केंद्र द्वारा गठित समिति को प्रेक्षित किये गए थे, जिनका शीघ्र निस्तारण कर किसानों को राहत प्रदान की जाए।

नोट :

- उन्होंने नेचुरल फार्मिंग एवं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना को शीघ्र लागू किये जाने का सुझाव भी दिया।
- उन्होंने राज्य में हो रही जैतून की खेती के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विस्तृत अध्ययन एवं अनुसंधान तथा रबी के मौसम में राज्य में मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करने की आवश्यकता भी बताई।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम व इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 1000 दर्शक क्षमता वाला यह नवीन ऑडिटोरियम लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा।
- लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल, वालीबॉल, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक, योगा, एरोबिक आदि खेलों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के लोगो और टी-शर्ट का विमोचन किया तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित एवं पदक विजेताओं को चैक प्रदान कर पुरस्कृत किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल को बाड़मेर ज़िले के लिये रवाना किया।
- मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के अहिंसा पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। लगभग 61 लाख रुपए की लागत से नव-निर्मित अहिंसा पार्क में 29 पेडेस्टल बनाकर महात्मा गांधी की जीवनी का विवरण लिपिबद्ध करवाया गया है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संभाग मुख्यालय स्थित डॉ. करणी सिंह स्टेडियम परिसर में बनने वाले मल्टीपरपज इंडोर हॉल का भी शिलान्यास भी किया।
- लगभग 7.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉल में खिलाड़ियों को टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी सहित विभिन्न इंडोर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकेगी।

ट्रैवल प्लस लेज़र की विश्व के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत् में प्रतिष्ठित मैगज़ीन ट्रैवल प्लस लेज़र द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के जयपुर को 8वाँ और उदयपुर को 10वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- इस सूची में प्रथम स्थान पर ओक्साका (मेक्सिको), दूसरे स्थान पर सैन मिगुएल डी ऑलेंडे (मैक्सिको), तीसरे स्थान पर उबुद (इंडोनेशिया), चौथे स्थान पर फ्लोरेंस (इटली) और पाँचवें स्थान पर इस्तांबुल (तुर्की) रहा।
- इसी प्रकार छठे स्थान पर मैक्सिको सिटी (मैक्सिको), सातवें स्थान पर चियांग माई (थाईलैंड) और नौवें स्थान पर ओसाका (जापान) रहा है।
- ट्रैवल प्लस लेज़र मैगज़ीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची भी जारी की गई है।
- टॉप शहरों की सूची में जयपुर को तीसरा और उदयपुर को पाँचवा स्थान मिला है। इस सूची में टॉप शहर उबुद (इंडोनेशिया), दूसरे स्थान पर चियांग (थाईलैंड) और चौथे स्थान पर ओसाका (जापान) रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा, नई पर्यटन नीति, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति सहित कई नवाचार किये जा रहे हैं।

नोट :

18वाँ अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

16 से 17 जुलाई, 2022 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) द्वारा 18वाँ अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समापन सत्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत से अब तक विभिन्न प्रकार के नवाचार किये गए हैं, जिससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है।
- उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित आउटरीच कार्यक्रम के तहत देश के सभी गाँवों में न्यायालयों के लंबित मामलों को निपटाया गया। प्राधिकरण द्वारा लगाई गई, लोक अदालतों द्वारा लंबित मामले का निस्तारण किया गया है। प्राधिकरण का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवाएँ प्रदान करना है।
- समापन सत्र में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, पंजाब व हरियाणा राज्य के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा तथा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
- इस अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने बालस्वराज-पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल तथा न्याय रो साथी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया एवं ई-पाठशाला कैंपेन का शुभारंभ किया।
- इसके अतिरिक्त रालसा के डिजिटल पहल आरएसएलएसए-22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म का भी लोकार्पण किया गया।

डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू किये गए 'ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट' की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने बाड़मेर और जैसलमेर ज़िलों में 'डेजर्ट नेशनल पार्क' में जैव-विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिये शुरू किये गए 'ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट' की तैयार कार्य योजना की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने दोनों ज़िलों के कलेक्टर्स को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता में लेने के निर्देश दिये।
- बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि जैसलमेर एवं बाड़मेर ज़िलों की 52 ग्राम पंचायतों के 10 हज़ार 400 कृषक परिवारों के लिये स्थानीय खरीद को सुगम बनाने के साथ स्थानीय उपज की खरीद और उनका बाज़ार से जुड़ाव के प्रयास किये जाएंगे।
- इस प्रोजेक्ट के तहत किसान पाठशालाओं के आयोजन से ग्रामवासियों के जीवनस्तर को उठाया जाएगा, साथ ही 6 हज़ार परिवारों के पोषण में वृद्धि के लिये उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। 200 प्राणिमित्रों, पशु सखियों को किसानों की सहायता के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट के तहत हरित परिदृश्य परियोजना द्वारा संबंधित गाँवों के 50 परिवारों को कृमि मुक्ति और पशुओं के टीकाकरण से लाभान्वित किया जाएगा। फार्म्स फील्ड स्कूलों के माध्यम से जैव-विविधता और स्थानीय संरक्षण के प्रयास किये जाएंगे।
- बैठक में कृषि आयुक्त कानाराम ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जैव-विविधता और वन परिदृश्य का संरक्षण करना है। 4 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की वर्ष 2026 तक पूरे होने की संभावना है।
- प्रोजेक्ट के तहत आने वाले गाँवों में पारंपरिक प्राकृतिक स्रोतों, जैसे- गोचर, ओरण एवं टांका आदि को पुनर्जीवित किया जाएगा। गाँवों में विलायती बबूलों को हटाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

नोट :

प्रदेश में खुलेंगे 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय व जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।
- प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएँ ली जाएंगी। इन न्यायालयों की समयावधि 09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष की होगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के उन ज़िलों में, जहाँ एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पायलट स्टडी विशेष न्यायालय खोले जाने हैं।

छबड़ा एवं कालीसिंध में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट होंगे स्थापित

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा तथा कालीसिंध में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार कर 06 करोड़ रुपए लागत की 660-660 मेगावाट क्षमता की 2 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित इकाइयाँ स्थापित होंगी।
- इसके साथ ही कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए 58 करोड़ रुपए लागत की 800 मेगावाट क्षमता की 1 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई स्थापित हो सकेगी।
- प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में छबड़ा एवं कालीसिंध में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने से जहाँ राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा, वहीं स्थानीय क्षेत्र के विकास एवं रोज़गार के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की बचत, प्रदूषण में कमी एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु घोषणा की थी।

नई दिल्ली में कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2022 को राजस्थान के कालबेलिया समुदाय के उत्थान के प्रयास की दिशा में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- कालबेलिया क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट प्रदर्शनी कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले हस्तशिल्प उत्पादों, विशेषकर कालबेलिया रजाईयाँ और गुदड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम साबित होगी।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि राजस्थान का कालबेलिया समुदाय अपनी कला के लिये पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उनके रोज़गार के संसाधन सीमित होने और आर्थिक तंगी के कारण उनकी कला एवं शिल्प को बाज़ार तक पहुँचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- प्रदर्शनी के क्यूरेटर डॉ. मदन मीना ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना कोविडकाल से विकसित हुई थी, जब राजस्थान के कालबेलिया के कई परिवार तालाबंदी के कारण अपने पैतृक गाँव लौट आए थे। कालबेलिया कलाकारों का काम भी पर्यटन की सुस्ती के कारण ठप हो गया। ऐसे में उन्हें उनके गाँव के भीतर वैकल्पिक आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिये कोटा हैरिटेज सोसाइटी द्वारा कालबेलिया क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी।
- इसे शुरू में निफ्ट-जोधपुर केंद्र और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर द्वारा अपने छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिये स्पॉन्सर किया गया था। वर्तमान में बूंदी और जयपुर की कालबेलिया महिलाएँ इस परियोजना में काम कर रही हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य कालबेलिया समुदाय की रजाई बनाने की परंपरा को संरक्षित करना और उन्हें अपने समुदाय एवं उनके शिल्प के निर्वाह के लिये उनके गाँवों के भीतर बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
- डॉ. मदन मीना ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कालबेलिया महिलाओं को विभिन्न कलात्मक उत्पाद बनाने के लिये प्रतिदिन 300 रुपए प्रति महिला दिया जाता है। इस धनराशि को विभिन्न स्रोतों से जुटाया जाता है तथा स्पॉन्सरशिप से भी धनराशि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिये किया जा रहा है।
- इस परियोजना में भाग लेने वाली कालबेलिया महिलाओं में जयपुर से मेवा सपेरा, बूंदी से मीरा बाई, लाड बाई, रेखा बाई, नट्टी बाई और बनिया बाई प्रमुख रूप से शामिल हैं।
- कार्यक्रम में जयपुर से आई अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम कालबेलिया गायक और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकीं मेवा सपेरा ने बताया कि कालबेलिया रजाई और उनकी गुणवत्ता घर की महिलाओं की समृद्धि, कौशल और प्रतिभा को दर्शाती है। एक परिवार रजाई के ढेर रखता है, जो मेहमानों की यात्रा के दौरान बाहर निकाला जाता है। ये रजाईयाँ बेटियों को उपहार देने का हिस्सा होती हैं।
- उन्होंने बताया कि खाली समय में कालबेलिया समुदाय की महिलाएँ अपने संग्रह के लिये हमेशा रजाई बनाती हैं। एक रजाई या गुदड़ी को पूरा होने में दो से तीन महीने का समय लगता है।

उत्सव पोर्टल पर राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी, राजस्थान चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'उत्सव पोर्टल' पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। इस सूची में केरल को दूसरा, उत्तर प्रदेश को तीसरा व अंडमान और निकोबार को चौथा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किया है।
- राजस्थान अपने समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों, महलों, स्वादिष्ट व्यंजन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिये देश-दुनिया में जाना जाता है।
- राजस्थान में श्री गोविंद देवजी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर (जयपुर) जैसे कई धार्मिक स्थलों के लाइव दर्शन लिंक के अलावा पुष्कर मेला (अजमेर), मेवाड़ उत्सव (उदयपुर), तीज उत्सव (जयपुर), कुंभलगढ़ उत्सव (राजसमंद), ब्रज होली महोत्सव (भरतपुर), गणगौर उत्सव (जयपुर), मरू महोत्सव (जैसलमेर) जैसे कई मेलों और उत्सवों की सूचना पोर्टल पर दर्ज की गई है।
- उल्लेखनीय है कि उत्सव पोर्टल वेबसाइट एक डिजिटल पहल है। इसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटकों की मदद के लिये कोरोना महामारी के समय वर्ष 2021 में शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया में लोकप्रिय बनाने, मेलों, त्योहारों और प्रमुख मंदिरों में होने वाली पूजा-अर्चना, आरती का लाइव प्रसारण करना है, ताकि लोग घर बैठे इनका आनंद उठा सकें। साथ ही उन्हें आगामी यात्रा कार्यक्रम को बनाने में आसानी हो।

नोट :

- उत्सव पोर्टल पर पर्यटन संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। पोर्टल पर आधिकारिक सोशल मीडिया लिंक, आधिकारिक वेबसाइटें, विवरणिका और आयोजन समिति के संपर्क विवरण तथा हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आसानी से गंतव्य तक पहुँचने की जानकारी प्रदान की जा रही है। इससे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक पहुँचने की योजना बनाने में सहायता मिल रही है।
- वेबसाइट पर 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों के विभिन्न धार्मिक मंदिरों की पूजा-आरती, पर्यटन स्थलों, कार्यक्रमों, मेलों और उत्सवों के लाइव दर्शन की जानकारी दी गई है। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट को लगातार अपडेट किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में आने वाले सभी मेलों और उत्सवों से संबंधित नई जानकारी तेज़ी से वेबसाइट पर अपडेट की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने किया जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीकर में बनने वाले जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राज्य के बजट में 17 ज़िलों में ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा यह ऑडिटोरियम 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है तथा इसमें 800 लोगों के बैठने की क्षमता है।
- इस ऑडिटोरियम में स्थानीय स्थापत्य कला के अनुसार आर्ट गैलरी, पुस्तकालय, 22 गेस्ट रूम, 2 बेन्क्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम एवं ऑफिस का निर्माण होगा। इसमें आधुनिक तकनीक के अनुरूप सभी ऑडियो-वीडियो और लाइव कार्यक्रम की व्यवस्था होगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीकर के काशी का वास गाँव में जन्में जमनालाल बजाज का आज़ादी के आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- जमनालाल बजाज ने गांधीजी के जीवन मूल्यों से प्रभावित होकर अपनी पत्नी एवं बच्चों सहित आश्रम में रहना शुरू कर दिया था तथा स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए थे। वर्धा में उन्होंने छूआछूत निवारण के लिये लक्ष्मीनारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराया था।

राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई-उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधिपति शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि मोटर-वाहन अधिनियम के अंतर्गत छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिये ई-कोर्ट परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट की एक नई अवधारणा पेश की गई है। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में उल्लंघनकर्त्ता या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त करना और न्यायालय के समय एवं जनशक्ति की बचत करना है।
- उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के तहत यातायात शाखा, जयपुर और जयपुर के विभिन्न पुलिस थानों से ऑनलाइन बनाए जाने वाले सभी चालान, ई-चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे। वर्चुअल कोर्ट उनके संबंध में ऑनलाइन ही न्यायिक आदेश पारित कर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।
- आम व्यक्ति को मैसेज के माध्यम से न्यायिक आदेश की सूचना प्राप्त होगी और ऑनलाइन जुर्माना राशि जमा करा कर ई-चालान का निपटारा करवाया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से जहाँ पुलिस विभाग और न्याय विभाग को सहूलियत होगी, वहीं जनता को भी काफी सुविधा होगी।
- जयपुर ज़िला के मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम-2 को वर्चुअल कोर्ट का प्रभार दिया गया है। इसके लिये ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, जिसका विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

नोट :

- इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे-छोटे मामले, जिनका निस्तारण मात्र जुर्माना राशि जमा करने पर ही हो सकता है के लिये आम जनता को न्यायालयों मे आकर लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुज़रने से बचाना और न्यायालयों में इन प्रकरणों के दर्ज होने से निस्तारण होने तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाना है, ताकि बचे समय का उपयोग गंभीर एवं पुराने मामलों के निस्तारण के लिये किया जा सके।

जोधपुर में बनेगी पैरा खेल अकादमी

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों हेतु पैरा खेल अकादमी की स्थापना के लिये 14 करोड़ रुपए की राशि को मंज़ूरी दी। इस अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण व अभ्यास हेतु आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव अनुसार, यह अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर, जोधपुर में स्थापित होगी तथा महाविद्यालय परिसर में आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचा तैयार होने तक इसे उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में संचालित किया जाएगा।
- इस अकादमी में राजस्थान राज्य के प्रतिभावान 25 खिलाड़ियों (15 शूटिंग व 10 टेबल टेनिस) का चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों को शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, आवास व्यवस्था, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधाएँ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त निर्धारित समय अनुसार प्रात: एवं सायं को प्रशिक्षकों द्वारा खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों को शिक्षा हेतु नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हुए खेल के साथ शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अकादमी के आवर्तक व अनावर्तक व्यय, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, खेल उपकरण की खरीद एवं छात्रावास भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जा सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पैरा खिलाड़ियों के लिये जयपुर व जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की थी। इससे पूर्व भी बजट घोषणा वर्ष 2020-21 व 2021-22 के अंतर्गत कई महत्त्वाकांक्षी खेल परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

'पैलेस ऑन व्हील्स' फिर से दौड़ेगी पटरियों पर

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की पहचान 'पैलेस ऑन व्हील्स' ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नज़र आएगी और पर्यटकों को इसमें यात्रा करने का अवसर मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- धर्मेंद्र राठौड़ ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम संचालन मंडल की 188वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
- उन्होंने कहा कि 'पैलेस ऑन व्हील्स' देश-विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। निगम द्वारा ट्रेन को फिर से शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने पैलेस ऑन व्हील्स को ओ एंड एम मॉडल पर देने की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे प्रदेश में पर्यटन इकाईयों की स्थापना में मदद मिलेगी, साथ ही पहले से चल रही पर्यटन इकाईयों को भी लाभ मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश में निवेश सहित रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- उन्होंने कहा कि मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच हेरिटेज रेल नेटवर्क विकसित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- भारतीय रेल (Indian Railways) और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDS) द्वारा संचालित यह शाही ट्रेन कोरोना महामारी के कारण बंद कर दी गई थी। यह शाही ट्रेन सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर है।

नोट :

- राजशाही सुविधाओं से भरपूर यह ट्रेन सितंबर से अप्रैल के दौरान चलती है। नई दिल्ली से अपनी आठ-दिवसीय यात्रा पर निकलती है। कुल 3,000 किमी. की यात्रा में ट्रेन दिल्ली से पिंकसिटी जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए वापस दिल्ली आती है।
- गौरतलब है कि दुनिया की जानी-मानी पर्यटन पत्रिका 'कोंडे नास्ट' द्वारा राजस्थान की सैर कराने वाली इस लग्जरी ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' को दुनिया की दूसरी लग्जरी ट्रेवल ट्रेन का दर्ज़ा दिया जा चुका है।

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट- 2022

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने होटल क्लार्क्स, आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- आरडीटीएम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- इस अवसर पर राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किया गया और यूनेस्को के साथ इंटैंजबल कल्चरल हेरिटेज के लिये किये गए एमओयू से संबंधित बुकलेट जारी की गई।
- डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है, इसलिये पर्यटन क्षेत्र के अनुकूल बजट घोषित किया गया था। राज्य सरकार की पर्यटन संबंधी दूरदर्शी नीतियाँ, नवाचार प्रदेश को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में लाभदायी होंगे।
- मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार पर्यटन विकास कोष में 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग व ब्रांडिंग के लिये खर्च किये जाएंगे।
- पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म-फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिये गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही प्रदेश को सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना है।
- यह नीति राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाली राजस्थानी भाषा की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित और राज्य में फिल्म उद्योग से संबंधित रोज़गार के अवसर सृजित करने में सहायक होगी।
- एफएचटीआर के अध्यक्ष अपूर्व कुमार ने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप उद्योग को पुनर्जीवित करने का तरीका है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 संबंधित ट्रैवल पार्टनर्स के लिये बातचीत और व्यापार सृजन हेतु एक सामान्य मंच के रूप में काम करने के लिये उपयुक्त होगा।
- गौरतलब है कि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, किले, महलों, कला और संस्कृति, वन्य जीवन, मेलों और त्योहारों, एडवेंचर, शादी, फिल्म शूट स्थलों के लिये देश-दुनिया में जाना जाता है।

उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में बनेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन निर्माण के लिये37 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस मंज़ूरी से बार काउंसिल के नवीन भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रांग रूम, विद्युत कक्ष व स्टाफ रूम आदि का निर्माण तथा भूतल पर बार काउंसिल के सचिव व पदाधिकारियों के कक्ष एवं अन्य सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
- इसके प्रथम व द्वितीय तल पर काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, ड्राइवर डोरमेटरी, मल्टीपरपज हॉल तथा ऑफिस आदि का निर्माण कराया जाएगा।
- इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में इस संबंध में 8.53 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की गई थी। ऑडिटोरियम एवं निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के कारण सुविधाओं का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने 14.37 करोड़ रुपए की संशोधित राशि के लिये स्वीकृति प्रदान की है।

18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी के पोस्टर का विमोचन किया। राष्ट्रीय जंबूरी 4 से 10 जनवरी, 2023 तक पाली ज़िले के रोहट में आयोजित होगी।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 66 साल बाद पुन: राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली है। इससे पहले संगठन को 1956 में राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली थी।
- इस 7 दिवसीय जंबूरी में स्टेट ट्वार, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
- इस जंबूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35 हज़ार स्काउट व गाइड शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जंबूरी के आयोजन के लिये 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी।

राज्य में प्रथम महिला निधि वित्तीय संस्थान के लिये एमओयू

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा 'महिला वित्तीय संस्थान' स्थापित करने के लिये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्रीनिधि तेलंगाना के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुए इस एमओयू पर राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल एवं तेलंगाना की ओर से स्त्रीनिधि के एमडी जी. विद्यासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किये।
- राज्य में 'राजस्थान महिला निधि' की स्थापना तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था के रूप में राजीविका के माध्यम से की जा रही है। राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसके सदस्य होंगे।
- राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपए (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपए) का अनुदान दिया जाएगा एवं भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए के अनुदान हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किये गए हैं।
- इस निधि के संचालन के लिये चरणबद्ध तरीके से राजीविका द्वारा 561 प्रोन्नत संकुल स्तरीय संघ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) से 10 लाख रुपए प्रति संकुल स्तरीय संघ शेयर कैपिटल के रूप में योगदान दिया जा रहा है।

नोट :

- महिला निधि के माध्यम से 40,000 रुपए तक के ऋण 48 घंटे में एवं इससे अधिक राशि के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में वितरित हो सकेंगे।
- इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा कि महिला निधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलेगा और उन्हें अपने उद्यम के लिये ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी। बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी।
- राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इस निधि का संचालन एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एसएचजी की महिलाओं के लिये ही किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किये जाने के संबंध में घोषणा की गई थी।

'घर-घर औषधि योजना' का होगा विस्तार

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'घर-घर औषधि योजना' का विस्तार कर नए रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इससे 'हरित राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान'की संकल्पना के तहत प्रदेशभर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिये 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाएंगे। इनमें से 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग अनुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेशवासियों को जनाधार कार्ड के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पौधे वितरित किये जाएंगे। आमजन को पौधे सरकारी नर्सरियों से मिलेंगे तथा दूरी की समस्या होने पर अन्य स्थानों से भी वितरण किया जा सकेगा।
- सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण के लिये राज्य की 10 हज़ार ग्राम पंचायतों को गोचर/ओरण/चारागाह हेतु तैयार किये गए एक करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक हज़ार पौधे उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार 200 बड़े नगरीय क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ पौधे प्रतिवर्ष लगाए जाएंगे।
- नवीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिये भी 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाएंगे तथा वर्ष 2022-23 में लगाए गए पौधों के लिये 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

'राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर्स रूल्स, 2017' में संशोधन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर्स रूल्स, 2017' में संशोधन को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी, जो राजस्थान के मूल निवासी हों, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति दी जा सकेगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन की दिशा में किये गए इस निर्णय से पदक विजेता खिलाड़ी समान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी करते हुए बेहतर रूप से अभ्यास कर सकेंगे तथा अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकेंगे।

नोट :

- गौरतलब है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। इन पदक विजेताओं को 'राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर्स रूल्स, 2017' के तहत उनकी प्रथम वरीयता अनुसार आनुपातिक रूप से विभागों का आवंटन किया गया था।

राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नशे पर नियंत्रण के लिये शीघ्र ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स विशेष रूप से नशे के कारोबार पर नियंत्रण करने का कार्य करेगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित चौथी राज्यस्तरीय एनकोर्ड (नारको कोऑर्डिनेशन) बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
- बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गृह विभाग को नशे के प्रति जागरूकता लाने के लिये शीघ्र ही राज्य स्तरीय जागरूकता रणनीति तैयार करने तथा युवाओं में बढ़ते मेडिसिनल नशे पर नियंत्रण के लिये प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये।
- उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 12 से 15 अगस्त तक स्कूली बच्चों के लिये आयोजित कार्यक्रमों में नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई जाए और इस शपथ को प्रदेश में अगस्त माह के अंत में प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे।

परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में महिलाओं के लिये परिवार नियोजन साधन 'अंतरा गर्भनिरोधक इंजेक्शन'की सुलभ सेवाएँ सुनिश्चित करने की उपलब्धियों हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पंवार ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। राजस्थान को मिले द्वितीय स्थान का यह पुरस्कार निदेशक आरसीएच डॉ. के. एल. मीणा एवं परियोजना निदेशक परिवार कल्याण डॉ. गिरीश द्विवेदी ने ग्रहण किया।
- राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने बताया कि प्रदेश में परिवार कल्याण साधन अंतरा इंजेक्शन की सुलभ उपलब्धता, फालोअप एवं सघन मॉनिटरिंग हेतु अंतराराज एप्लीकेशन, ई-काउंसिलिंग, ई-लर्निंग मॉड्यूल को क्रियान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक महिलाओं ने इस साधन को अपनाया है। अब तक कुल 10 लाख अंतरा इंजेक्शन की डोज लगवाई गई हैं।
- गौरतलब है कि अंतरा इंजेक्शन अनचाहे गर्भ को रोकने व बच्चों के बीच अंतर रखने का एक सुरक्षित अस्थायी गर्भनिरोधक विकल्प है। तीन माह के अंतराल में लगने वाला यह इंजेक्शन एक बार लगवाने पर तीन माह तक या 90 दिन तक अनचाहे गर्भ से छुटकारा देता है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में संशोधन को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उक्त संशोधनों से खनिजों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसों की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी।
- संशोधित नियमावली में अप्रधान खनिजों के खनन पटों के हस्तांतरण पर लिये जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेंट/लाईसेंस फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रुपए के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रुपए तक लिया जाएगा तथा पट्टाधारियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के लिये मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा।
- नए नियमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा को भी हटाया जा सकेगा, ताकि वैज्ञानिक और सुरक्षित खनन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर अप्रधान खनिज के खनन पट्टों /क्वारी लाईसेंस के समीप उपलब्ध भूमि एक निश्चित क्षेत्रफल तक खनन पट्टों/लाईसेंस धारी को आवंटित की जा सकेगी।
- सुगमता की दृष्टि से नवीन प्रावधान के अनुसार खानों का पंजीयन बिना पर्यावरण अनुमति के हो सकेगा, लेकिन खनन कार्य पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही शुरू होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की क्रियान्विति में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंज़ूरी दी है।

हेपेटाइटिस अभियान के तहत राजस्थान को मिला राष्ट्रीय सम्मान

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को हेपेटाइटिस अभियान के तहत सघन स्क्रीनिंग एवं व्यापक जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित करने के लिये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा-पत्र प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसी प्रकार हेल्दी लीवर कैंपेन के अंतर्गत प्रदेशभर में बेहतरीन कार्य करने वाले चिकित्सकों, जेल अधीक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं ज़िला आईईसी समन्वयकों इत्यादि को सम्मानित किया गया।
- इस अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल गरीब-से-गरीब आदमी को भी पूर्णत: नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करवाता है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य को निरोगी बनाने के अभियान के शुरुआत 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना' से की थी। वर्तमान में 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना', 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना' के माध्यम से प्रदेशवासियों को नि:शुल्क जाँच, दवा एवं उपचार की सुविधा मिल रही है।
- अनियमित खानपान और शुद्ध पानी का उपयोग नहीं करने से हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी होती है। हम सभी को शराब, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि के सेवन से बचना चाहिये और स्वस्थ जीवन-शैली अपनानी चाहिये।
- जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हेल्दी लीवर कैंपेन के अंतर्गत जनसहभागिता से प्रदेश में 64 हज़ार 733 पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन करवाया गया है और नियमित अंतराल में जल शुद्धिकरण की गतिविधियाँ विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 33 ज़िलों में ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से भी पेयजल की जाँच का कार्य करवाया जा रहा है। राज्य की 11 हज़ार 325 ग्राम पंचायतों में से 6 हज़ार 938 ग्राम पंचायतों में पेयजल जाँच हेतु प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
- उन्होंने कहा कि विभिन्न जल स्रोतों से प्राप्त जल का शुद्धिकरण कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से हेपेटाइटिस ए एवं ई की रोकथाम सुनिश्चित होगी तथा संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी आएगी।

नोट :

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एवं एनएचएम मिशन निदेशक रोली सिंह ने कहा कि 'तंबाकू नियंत्रण अभियान' की तरह ही राजस्थान में 'नेशनल वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत 'हेल्दी लीवर कैंपेन' का सफल संचालन कर आमजन में इसके बारे में जागरूकता विकसित की गई है।

भीलवाड़ा ज़िले के मांडल में 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा ज़िले के विधानसभा क्षेत्र मांडल में 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- यह राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है, जहाँ बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई हैं। गली- मोहल्लों और घरों की छतों पर अब लटकते तार नहीं दिखेंगे तथा बिजली संबंधी दुर्घटनाएँ भी घटित नहीं होंगी।
- 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस ग्रिड की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- राजस्व मंत्री ने कहा कि ज़िले में 132 केवी के 9 ग्रिड तथा 33 केवी के 87 ग्रिड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गए। मांडल में 33 केवी के विद्युत ग्रिड से यहाँ के छोटे उद्योगों व घरों को बिजली की सुविधा मिलेगी।
- डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता शीशराम वर्मा ने बताया कि मांडल गाँव में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रखने के लिये 33/11 जीएसएस का निर्माण किया गया है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से यूआईटी के माध्यम से 3 किमी. 11 केवी व 15 किमी. एलटी अंडर ग्राउंड कर दी गई है।

चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने शासन सचिवालय में नंद घर योजना की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि योजना के तहत 25 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध नंद घर के रूप में विकसित किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में 25 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को 'नंद घर' के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी।
- मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के तहत चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन अपग्रेडेशन, ई लर्निंग सामग्री के वितरण के लिये एलईडी प्रोजेक्टर, पानी का शुद्धिकरण यंत्र सहित विभिन्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँ।
- उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी भी बनाई जाए। ज़िला कलेक्टर द्वारा भी चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी, बिजली, इंटरनेट कनेक्शन सहित विभिन्न कार्य किये जाएँ।
- महिला एवं बाल विकास सचिव दिनेश कुमार यादव ने बताया की बजट घोषणा 2021-22 की पालना में 25 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिये राज्य सरकार तथा वेदांता लिमिटेड के मध्य 8 फरवरी, 2022 को एमओयू किया गया था।
- विभागीय भवनों, सरकारी भवनों तथा अन्य सामुदायिक भवनों में संचालित 32 हज़ार 507 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 26 हज़ार 6 को नंद घर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

नोट :

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा राज्यपाल ने पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धति एवं वैकल्पिक औषधि विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पण किया।
- राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि संविधान पार्क विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक आस्था को मज़बूत करने में सहायक होंगे। इससे युवा राष्ट्रबोध से जुड़कर देशहित में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित होंगे।
- राज्यपाल ने कहा कि इसके पीछे मूल भावना यह है कि देश के भावी नागरिक इन पार्कों का भ्रमण कर संविधान की उदात्त संस्कृति को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। उनमें मौलिक कर्त्तव्यों, नीति निदेशक तत्त्वों का समावेश हो और वे देश के प्रति ज़िम्मेदारी का अहसास करें।
- विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सतीश कुमार गर्ग ने कहा कि विश्वविद्यालय के सार्दुल सदन परिसर में निर्मित संविधान पार्क में संविधान स्तंभ बनाया गया है, जिस पर अशोक चिह्न एवं तिरंगा लगा है। मार्बल के पत्थर पर राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व, नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य को अंकित किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका पट्टी को मुख्य स्तंभ पर दर्शाया गया है।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने जयपुर में बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सेंटर का काम नवंबर तक पूरा करने के लिये जेडीए टाइमलाइन बनाकर काम करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने निर्देश दिया कि विश्वस्तर की सुविधाएँ विकसित करने के साथ ही सेंटर का संचालन और रखरखाव भी विश्व स्तर का होना चाहिये। सेंटर ऐसे केंद्र की तरह विकसित हो, जो देश-दुनिया में आइकॉनिक बने।
- उन्होंने कहा कि सेंटर को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज़ पर विकसित किया जाए। सेंटर के संचालन के लिये विशेष टीम बनाई जाए, जिसमें इस सेक्टर से जुड़े अनुभवी लोगों को जोड़ा जाए।
- जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन ने बताया कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पूरे प्रदेश की कला स्थापत्य की खूबसूरती एक छत के नीचे दिखेगी।
- यहाँ ऑडिटोरियम, कन्वेंशन हॉल, क्रॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ कॉन्फ्रेंस व सेमिनार के आयोजन की विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- ऑडिटोरियम की दीवारें जैसलमेर की पटवाओं की हवेली में बनी जाली पर आधारित होंगी। कन्वेंशन हॉल व प्री-फंक्शन एरिया में सिटी पैलेस के झरोखे व हवामहल की खिड़कियाँ दिखेंगी। मिनी ऑडिटोरियम को मारवाड़ पैटर्न के अनुसार बनाया गया है।
- कॉन्फ्रेंस हॉल को जोधपुर के मारवाड़ स्टाइल में बनाया जा रहा है, जहाँ मंडोर उद्यान के पारंपरिक मेहराब व स्मारक की झलक दिखाई देगी। सेंटर की ई-लाइब्रेरी पूरी तरह आधुनिक रूप में होगी, जहाँ देश और दुनिया की बेहतरीन किताबें उपलब्ध होंगी। सेंटर में लैक्चर रूम्स तथा रेस्टोरेंट्स का निर्माण भी किया जा रहा है।

नोट :